(b) if so, the details thereof;

(c) whether funds have been released for the purpose; and

(d) if not, by when the funds will be released?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) Allocation of funds to State Governments and Union Territories is made by Planning Commission. As per information furnished by Planning Commission, no request has been received from Gujarat Government for release of funds for magnetite mines in the State.

(b) to (d) Does not arise.

Deletion of Limestone and Bauxite

2448. SHRI PRAFULL GORADIA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the Government of Gujarat has represented to delete limestone and bauxite from the list of Scheduled minerals shown in Schedule I of MMRD Act, 1957; and

(b) if so, the decision thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) and (b) Yes, Sir. The proposal for deletion of Limestone and Bauxite from Schedule I of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, has been considered by the Committee constituted under the Chairmanship of the then Secretary (Mines) with the Secretaries of some of the State Governments including the Government of Gujarat, Secretary General, Federation of Indian Mineral Industries, Controller General, Indian Bureau of Mines etc. as members. The terms of reference of the Committee inter-alia, included review of the existing laws and procedures governing regulation and development of minerals and to recommend steps to make them compatible with the policy changes and to suggest steps to reduce delays in grant/renewal of Prospecting Licences/Mining Leases. The Committee was also to consider and suggest further delegation of powers to the State Governments regarding grant/renewal of Prospecting Licences/Mining Leases and measures to be taken to prevent illegal mining. The Committee has since submitted its report on which necessary action for amendment in the Mines and Minerals (Regulation & Development) Act, 1957 and Rules made thereunder has already been initiated.

इस्पात उद्योग की लघु और मझौली इकाइयां

2449. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के इस्पात उद्योग की लघु और मझौली इकाइयों को जो मन्दी के दौर से गुजर रही हैं, संगठित करने के लिए सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस्पात उद्योग की लघु और मझौली इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष प्रयास किये गये हैं;

(ग) क्या इस विकट परिस्थिति में राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा उनकी कटिनाइयां बढ़ाई जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उनको उचित दिशा-निर्देश दे रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) इस्पात उद्योग को जुलाई, 1991 से लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है और इस पर से नियंत्रण समाप्त कर दिया गया है। उद्योग के साथ-साथ इकाइयों का भविष्य पूरी तरह से बाजार परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

मौजूदा प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) इस्पात की मांग, विशेष रूप से गैर-परम्परागत क्षेत्रों जैसे ग्रामीण और कृषि आधारित औद्योगिक क्षेत्रों में, बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू करना।

(2) अनेक आदानों जैसे कोककर कोयला (12% से कम राखांश) अकोककर कोयला (12% से कम राखांश)

धातुकर्मीय कोक, फेरो निकेल, चार्ज निकेल और निकेल ऑक्साइड सिंदूर, न्यून सिलिकायुक्त चूना-पत्थर और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड (28 इंच से अधिक) पर विशेष आयात शुल्क समाप्त करना।

(3) पाटन-रोधी जांच तंत्र को सुदृढ़ करना और यूक्रेन और रूस से आयातित तप्त बेलित क्वायलों पर पाटन-रोधी-शुल्क लगाने की सिफारिश करना।

(4) निर्यात में वृद्धि करने हेतु इस्पात के निर्यात के लिए ड्यूटी एन्टाइटलमेंट पास बुक (डी०ई०पी०बी०) दरों को युक्ति संगत बनाना।

(5) निर्यात में अड़चनों का समाधान करने के लिए इस्पात के निर्यातकों की सहायता करने हेतु इस्पात निर्यातक मंच का गठन।

(6) इस्पात निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार करने और भारतीय इस्पात की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विशिष्ट अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की जांच करने तथा सहायता देने के लिए एक अधिकार-प्राप्त समिति का गठन करना।

(ग) से (ड़) विद्युत दरों में वृद्धि तथा घटिया गुणवत्ता से इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और इंडक्शन फर्नेस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। इस उद्योग को कुछ राहत प्रदान करने के लिए इस्पात विभाग राज्य सरकारों से दरों के ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के लिए अनुरोध करता रहा है।

Study Groups for Certain Policy Measures

2450. SHRI JIBON ROY: Will the Minister of STEEL AND MINES be plesed to state:

(a) whether the Steel Authority of India Ltd. has formed working groups to recommend certain policy measure on different aspects of its working;

(b) if so, the topics covered by the study groups and personnel appointed for the purpose; and

(c) when the working groups are likely to submit their recommendations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) to (c) Steel Authority of India Limited (SAIL) has formed seven working groups to identify Strategic Thrust Areas (STAs). Topics covered by these groups and personnel appointed for the purpose are given below:—

S.No.	Topics	Personal Appointed
1.	People Related Issues	(1) Managing Director, (2) Director (Personnel) SAIL
2.	Increase Market Share & Net Sales Realisation through Customer Satisfaction, Quality Assurance and Aggressive Selling Strategies	(1) Director (Commercial) SAIL (Managing Director, Bokaro Steel Plant
3.	Reduction of Costs	(1) Director (Operations) SAIL (2) Director (RDCIS), SAIL
4.	Full Capacity Utilisation of Modernised Units	(1) Managing Director, Durgapur Steel Plant
5.	Asset Restructuring	(1) Director (Projects), SAIL (2) Managing Director, Rourkela Steel Plant